GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 22 March, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 2 : Indian Polity	नागरिक समाज समूहों ने सरकार से आरटीआई अधिनियम को कमजोर न करने का आह्वान किया
Page 05 Syllabus : GS 2 : Indian Polity	2025 के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग प्रकाशित न करें: शिक्षा मंत्रालय से उच्च न्यायालय ने कहा
Page 05 Syllabus : Prelims fact	जीएम खाद्य फसलों पर प्रगति हुई है, अधिकारी ने कहा
Page 09 Syllabus : Prelims fact	लाल-तीखी बयादगी मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसानों को चुभन
In News	आसियान
Page 06 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Indian Polity	बजटीय मामलों में भारत की संसद हाशिए पर

It's about quality

Page 03 : GS 2 : Indian Polity

राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार परिषद (NCPRI) के नेतृत्व में 30 से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने केंद्र सरकार से सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को कमजोर न करने की अपील की है। उनकी मुख्य चिंता 2023 में पारित एक संशोधन को लेकर है, जो लागू होने के बाद सरकारी सूचनाओं तक पहुंच को काफी सीमित कर देगा।

Civil society groups call on govt. to not water down RTI Act

Aroon Deep
NEW DELHI

The exemption on providing personal information is on track to become a blanket prohibition

Over 30 civil society organisations are urging the Union government to avoid gutting the Right to Information Act, 2005, the National Council for People's Right to Information (NCPRI) announced on Friday. An amendment to the RTI Act passed in 2023 – which has not yet come into effect – would drastically limit the amount of information that government agencies would be required to share, activists said, upping pressure on the government to keep the law intact.

The issue is around Section 8(1)(j) of the RTI Act, which allows government agencies to refuse applications for information if they relate to an individual's personal information. "Studies show that this exemption is among the most common grounds to refuse information", Nikhil Dey, an NCPRI co-convenor, said at a press conference on Friday.

However, the section has a proviso, which allows for personal information to be disclosed if there is public interest in doing so. In 2023, the Union government, in spite of protests, removed the proviso through an Act of Parliament. This was done through the last section of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

Since the subordinate legislation for kicking in the DPDP Act has not yet been notified, the amendment has not kicked in. The draft DPDP Rules, 2025, should not notify this amendment, and Parliament should pass a law undoing the amendment from the Act as well, said Anjali Bhardwaj, co-convenor of the NCPRI.

मुख्य मुद्दा: RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j)

- **वर्तमान प्रावधान:** धारा 8(1)(j) के तहत, सरकार किसी भी व्यक्ति से संबंधित निजी जानकारी को साझा करने से इनकार कर सकती है। हालांकि, यदि सूचना को सार्वजनिक हित में आवश्यक माना जाता है, तो इसे साझा करने का प्रावधान है।
- **संशोधन का प्रभाव:** 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम ने इस प्रावधान को हटा दिया, जिससे अब किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा संभव नहीं होगा, भले ही वह सार्वजनिक हित में क्यों न हो।
- **वर्तमान स्थिति:** चूंकि DPDP अधिनियम के तहत अधीनस्थ कानूनों की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए यह संशोधन अभी प्रभावी नहीं हुआ है।

नागरिक समाज की चिंताएँ

- **पारदर्शिता पर खतरा:** यह संशोधन जवाबदेही को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी छिपा सकते हैं।
- **छूट प्रावधानों का दुरुपयोग:** अध्ययनों से पता चला है कि धारा 8(1)(j) का पहले से ही सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है और यह RTI आवेदनों को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण बन चुका है।
- **संशोधन की वापसी की मांग:** कार्यकर्ता चाहते हैं कि DPDP नियम, 2025 में इस संशोधन को शामिल न किया जाए और संसद एक नया कानून पारित कर इस प्रावधान को बहाल करे।

निष्कर्ष

- RTI अधिनियम में प्रस्तावित यह बदलाव महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तक पहुंच को सीमित कर सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होगी। नागरिक समाज संगठनों ने सूचना के अधिकार की रक्षा करने और इस संशोधन को वापस लेने की मांग की है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।

UPSC Mains Practice Question

Ques: सूचना का अधिकार (आरटीआई) शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सूचना तक नागरिकों की पहुँच पर आरटीआई अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों के प्रभाव पर चर्चा करें। **(250 words)**

It's about quality

Page 05 : GS 2: Indian Polity

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की रैंकिंग प्रकाशित करने से रोक दिया है। यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने रैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे।

Do not publish NIRF ranking for 2025: HC to Education Ministry

The Hindu Bureau
MADURAI

NIRF ranking is done based on the data given by institutions without verification, says petitioner

The Madurai Bench of the Madras High Court on Thursday restrained the Education Ministry and the National Board of Accreditation (NBA) from publishing the National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking for 2025.

The court was hearing a public interest litigation petition filed by C. Chellamuthu from Dindigul district of Tamil Nadu.

He claimed that the ranking was without any basis and was misleading students.

The NIRF was launched by the NBA on the direction of the Education Ministry for evaluating higher education institutions.

The NBA publishes the ranking every year. Institutions are evaluated on five broad categories – teaching, learning and resources; research and professional practice; graduation outcomes; outreach and inclusivity; and perception – the petition said.

The NBA directs institutions to upload data on student and staff strength, staff salaries, graduation index, placement details, funds received for research, and other parameters on its web portal. Based on this data, the ranking is awarded without further verification or auditing, the petitioner said.

Comparing it with the National Assessment and Accreditation Council's (NAAC) Annual Quality Assurance Report (AQAR), the petitioner said the NAAC-AQAR documents were audited and checked by expert committees sent by the NAAC to the institutions.

The petitioner sought a direction to the NBA to publish the NIRF ranking after comparing and verifying the data submitted by the institutions with the data in the government records and to disclose the calculation method.

A Division Bench of Justices J. Nisha Banu and S. Srimathy restrained the authorities from publishing the ranking for 2025. The court sought a counter affidavit and posted the matter to April 24.

याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

- **डाटा का सत्यापन नहीं किया जाता –** याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संस्थान छात्र संख्या, फैकल्टी सदस्यों, वेतन, शोध निधि, प्लेसमेंट और स्नातक परिणामों जैसे आंकड़ों को स्वयं रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी कोई बाहरी जांच या सत्यापन नहीं होता।
- **भ्रामक रैंकिंग प्रणाली –** बिना स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया के, ये रैंकिंग संस्थानों की वास्तविक गुणवत्ता को ठीक से नहीं दर्शा पाती, जिससे छात्र और अन्य हितधारक गुमराह हो सकते हैं।
- **NAAC प्रत्यायन से तुलना –** याचिकाकर्ता ने कहा कि, NAAC की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (AQAR) में विशेषज्ञ समितियाँ आंकड़ों का ऑडिट करती हैं, जबकि NIRF रैंकिंग बिना ऑडिटेड जानकारी पर आधारित होती है।
- **पारदर्शिता की माँग** – याचिकाकर्ता ने सरकारी रिकॉर्ड से डाटा का सत्यापन करने की व्यवस्था लागू करने और रैंकिंग में प्रयुक्त गणना विधि को सार्वजनिक करने की माँग की।

न्यायालय की प्रतिक्रिया

- न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और एस. श्रीमथी की खंडपीठ ने NIRF 2025 रैंकिंग के प्रकाशन पर अस्थायी रोक लगा दी।
- प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया कि वे रैंकिंग प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करें।
- मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल 2025 को होगी।

आगे का रास्ता

- NIRF रैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना, जिसमें थर्ड-पार्टी ऑडिट को शामिल किया जाए।
- डाटा पारदर्शिता को बढ़ाना, जिससे रैंकिंग की गणना विधि और कच्चे डाटा को सार्वजनिक किया जाए।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप सुधार सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

- अदालत का यह हस्तक्षेप संस्थागत रैंकिंग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। यह स्पष्ट करता है कि डेटा सत्यापन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि छात्रों और शैक्षिक संस्थानों के लिए निष्पक्ष और भरोसेमंद रैंकिंग प्रणाली तैयार की जा सके।

UPSC Mains Practice Question

Ques : भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? **(250 words)**

Page 05 : Prelims fact

भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2022 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा GM सरसों को दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने कहा है कि इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, हालांकि कानूनी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बनी हुई हैं।

There is progress on GM food crops, says official

Remark comes amid apprehensions over the Environment Ministry's approval for commercial cultivation of GM mustard in 2022; Supreme Court is set to hear pleas on the same next month

Jacob Koshy
NEW DELHI

Ahead of a fresh series of hearings in the Supreme Court next month over genetically modified (GM) food crops, the Department of Biotechnology (DBT) said there was "progress" on this front.

"The matter is *sub judice* but GM mustard stories are being taken up again," DBT Secretary Rajesh Gokhale said at a biotechnology event on Friday. The DBT, which has for years funded research and development into transgenic and GM food crops, comes under the Ministry of Science and Technology.

At present, Bt cotton is the only genetically modified crop allowed to be cultivated. Though the Environment Ministry gave its conditional go-ahead for commercial cultivation of GM mustard in 2022, it has not taken off as it was challenged in the Supreme Court.

Science Minister Jitendra Singh who was also at the event, said, "There is so much dynamism in biotechnology development that we cannot look at tomorrow through the prism of today."

Awaiting hearing: Petitioners have challenged the Environment Ministry's approval for cultivation of GM mustard. R.V. MOORTHY

Hearing from April 15

On March 6, a three-judge Bench of the Supreme Court said it will begin hearing from April 15 petitions challenging the Environment Ministry's approval for cultivation of GM mustard. The court has told all parties to file their written submissions within a week.

A two-judge Bench of the top court, on July 23, 2024, gave a split verdict on the validity of the Centre's 2022 decision granting conditional approval for the environmental release of GM mustard crop. However, it also directed the Centre to formulate a "national policy" on GM crops. Mr. Gokhale told *The Hindu* that the DBT had provided "technical inputs" to the Union Environment Ministry, which was formulating the policy and was the "nodal coordinator".

Safety concerns

GM mustard, developed using public funds, was the first transgenic food crop to be approved for farmer fields by the Genetic Engineering Appraisal Committee, a scientific body. However, it wasn't approved for cultivation following safety objections by activist groups.

However, the use of biotechnology to improve food crops – as in the case of GM mustard – is a key focus of the government's BioE3 policy.

This involves manufacturing new kinds of enzymes, pharmaceuticals and agricultural products while applying techniques, including genetic engineering.

A report released by the DBT at the event on Friday on the current state of India's 'bio-economy' says that bio-agriculture accounts for 8.1% – the smallest share – of the $165.7 billion bio-economy in India.

"Valued at $13.5 billion, this segment enhances agricultural productivity and resilience through genetically modified crops like Bt Cotton and precision agriculture technologies," the report notes.

भारत में GM फसलों की वर्तमान स्थिति

- Bt कपास भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है।

- जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) ने 2022 में GM सरसों को शर्तों के साथ मंजूरी दी थी, लेकिन कानूनी चुनौतियों के कारण इसकी खेती अब तक शुरू नहीं हो सकी।
- सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल 2025 से GM सरसों की मंजूरी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
- जुलाई 2024 में आए एक विभाजित फैसले में कोर्ट ने सरकार को GM फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया था।

मुख्य बहस के मुद्दे

- **वैज्ञानिक और आर्थिक लाभ**
  - GM फसलें कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कीटों व जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता विकसित करने में मदद कर सकती हैं।
  - सरकार की BioE3 नीति खाद्य फसलों, एंजाइम उत्पादन और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है।
  - DBT के अनुसार, जैव-कृषि का योगदान भारत की $165.7 बिलियन की जैव-अर्थव्यवस्था में केवल 8.1% है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की संभावना है।
- **सुरक्षा और पर्यावरणीय चिंताएँ**
  - कार्यकर्ताओं और पर्यावरण समूहों ने जैव-सुरक्षा, मूल प्रजातियों के संदूषण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर आपत्ति जताई है।
  - GM फसलों को मंजूरी देने से पहले अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन की माँग की जा रही है।
- **नियामकीय और कानूनी अनिश्चितता**
  - भारत में GM फसलों पर स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है, जिसके कारण बार-बार कानूनी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला GM खाद्य फसलों की मंजूरी के भविष्य को निर्धारित कर सकता है।

आगे का रास्ता

- GM फसलों पर एक समग्र राष्ट्रीय नीति बनाना, जिससे वैज्ञानिक नवाचार और सुरक्षा मानकों में संतुलन बना रहे।
- स्वतंत्र नियामक तंत्र को मजबूत करना, ताकि जैव-सुरक्षा आकलन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- जन-जागरूकता और हितधारकों के साथ परामर्श बढ़ाना, जिससे GM तकनीक में विश्वास स्थापित हो।

निष्कर्ष

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के कृषि जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। इससे नीति निर्माण, वैज्ञानिक शोध और जनता की GM फसलों को लेकर धारणा प्रभावित होगी। अब देखना होगा कि यह निर्णय वैज्ञानिक प्रगति और जैव-सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर पाता है या नहीं।

UPSC Mains Practice Question

Ques : भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों की भूमिका पर चर्चा करें। उन्हें अपनाने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? **(250 words)**

Page 09 : Prelims fact

ब्याडगी मिर्च किसानों को भारी मूल्य गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण अतिरिक्त उत्पादन, भंडारण की अधिकता और सख्त निर्यात नियम हैं।

The plunge: In February 2024, the average price for Byadgi Kaddi, Byadgi Dabbi, and Guntur varieties stood at ₹35,099, ₹38,951, and ₹13,509 a quintal, respectively. On Thursday, they were ₹23,359, ₹25,869, and ₹12,209, a quintal respectively. K MURALI KUMAR

Red-hot Byadgi chilli stings farmers as prices plummet

Byadgi chillies are a must in every kitchen for their special colour and flavour. But the growers of this variety in several parts of north Karnataka are in distress as prices are falling. **Girish Pattanashetti** travelled to the chilli market in Byadgi in Haveri district to talk to the farmers

It's Thursday noon at the APMC yard in Byadgi and police sub-inspector Arvind P.S. is giving instructions to police personnel about the first of the two route marches to be taken out in the market yard. A little later, the yard reverberates with the siren of the police vehicles which take the designated road of the route march. Farmers wait beside their heaps of bags of red chillies and look on anxiously.

"Don't worry, it is a routine exercise," Kanthesh, who works for a commission agent at the market yard, comforts an anxious farmer. The vehicles are back at the APMC office after the march and the personnel stand guard at vantage points. The exercise is repeated after 3 p.m.

In the market spread across 78 acres in Byadgi town of Haveri district in north Karnataka, the route march is taken out twice on Mondays and Thursdays when the chilli market is open. The Byadgi variety of chilli is known the world over for its colour and unique flavour.

Mounesh Acharya, a chilli farmer from Dommur in Ballari district, waits for bidders to arrive at the Byadgi APMC yard. GIRISH PATTANASHETTI

This has been the practice since March 11, 2024, the day when the APMC (Agricultural Produce Marketing Committee) office was torched and a few vehicles, including a fire engine, were gutted, says a policeman on duty, as several others, including a few who suffered minor injuries during the violence, keep vigil. The APMC office now wears a new look after a fresh coat of paint.

At a distance, sitting under the shade and standing by the roadside, first-time visitors to the market are being told tales of the violent protest a year ago, and the subsequent arrests and losses.

Meanwhile, unmindful of the siren, Basavaraj Navale, who works for the commission agents, and trader B.M. Chatrad are busy assessing the quality of the chilli kept for auction. The likes of Basavaraj, who are scattered over the big yard, have already completed the assessment of the quality of the chilli pods and have written down the bids for each lot they assessed. Traders and commission agents Basavaraj Chatrad and Malatesh Chatrad too are busy doing the same. However, their work is limited to the lots in the open space before their office.

Nothing much seems to have changed after the violence in the Byadgi APMC yard a year ago over the sudden dip in prices of different varieties of red chillies.

Downward trend

What has caused concern yet again this year is the further dip in the prices, leading to sporadic protests not in Byadgi but in far-off places like Kalaburagi and Raichur, where the Guntur variety has seen much lower bids. The series of meetings officials and Minister of Textiles, Sugarcane Development and Agricultural Marketing Shivanand Patil, had with farmers and APMC merchants, don't seem to have made any impact so far except for the increase in police bandobast. Cold storage in Byadgi promised by the Minister has not materialised as suitable land couldn't yet be found.

Workers unloading chilli bags at the Byadgi APMC yard on Thursday. GIRISH PATTANASHETTI

> Old stock is the biggest problem and what has affected the traders is that the crop, which they bought at a higher price and kept in cold storage, is now fetching even lower price.
>
> GANESH ACHALKAR, trader

In February last year, the average prices for Byadgi Kaddi, Byadgi Dabbi and Guntur stood at ₹35,099, ₹38,951 and ₹13,509, a quintal respectively. In February this year, the average prices for the same varieties were ₹27,009, ₹28,2098 and ₹13,900 a quintal respectively.

On Thursday, Byadgi recorded arrivals of 2,47,196 bags and the average prices for Kaddi and Dabbi varieties were ₹23,359 and ₹25,869 a quintal respectively, and the Guntur variety fetched average price of ₹12,209.

Last year, Byadgi yard recorded arrivals of 68,36,363 bags recording a turnover of ₹3,187.73 crore and this year, it seems to cross last year's arrivals. However, the turnover is less due to low prices.

Byadgi has not witnessed any protest over the prices this year but the pain is palpable on the faces of farmers who have travelled covering over 250 km carrying their produce in anticipation of a good price.

Last week, Parameshappa U. from Tangaradona in Kurnool district of Andhra Pradesh brought 50 bags of Byadgi Kaddi variety, which fetched ₹11,000 per quintal. On Thursday, he was back in Byadgi with 10 bags, but not sure about fetching the same price. His friend from the same village, Brahmanand Reddy, was too not hopeful.

"They say there is no demand and last year's stock is still in the cold storage," Parameshappa said. He has been coming to Byadgi since 1996 and the highest price he got was ₹48,000 for the native Byadgi Kaddi variety three years ago. But this year, he has incurred a loss of ₹1 lakh.

Sitting on the pile of bags and waiting for the bids to be made, Mounesh Acharya from Dommur village in Ballari district is also not that optimistic. "The cost of bringing one bag of red chillis to the Byadgi market is around ₹200. The expenditure per acre is between ₹1 lakh to ₹1.5 lakh. If I get ₹12,000 per quintal that will meet the expenses", he said.

Problem of plenty

Like last year, record arrivals and the problem of plenty have resulted in prices falling particularly for varieties developed by seed companies. What has added to the problems of farmers and traders is the stock of the previous two years.

"Nearly 40% of the previous years' stock has been carried over to this year and is still lying in the cold storage because of low prices," said Basavaraj Chatrad, president of the dispute redressal committee of the APMC Merchants Association.

"Old stock is the biggest problem and what has affected the traders is that the crop they bought at a higher price and kept in cold storage, is now fetching even lower price" said trader and commission agent Ganesh Achalkar.

Shivaraj Chatrad, who has returned to Byadgi to join his father in the trade, after his MBA in London, cites three reasons for the drop in prices. "One, the problem of old stock left with the traders. Two, the spice companies also have excess stock. And three, increased quantum of rejection in exports due to stringent test parameters introduced of late."

Tougher testing parameters

Western countries have made the testing parameters stringent after traces of cancer-causing agents were found in exported consignments. While Asian countries have less strict testing parameters, they too have problem of plenty, he says.

Secretary of APMC Merchants Association, Byadgi V.S. Morigeri (Raju) believes the use of banned pesticides by farmers is the major reason for increase in the instances of rejection of export consignments. "50% of the chillies procured in Byadgi APMC Market are exported in different forms like destemmed pods, extracted colour and Oleoresin capsicum. However, because of good stock, the companies involved are demanding high-quality pods at lower prices this year," he said.

Another reason for the lesser demand for the Byadgi Dabbi and Kaddi varieties is that the high prices these varieties fetched during the previous years made the companies switch to other affordable varieties with less colour.

Is there a solution?

As of now, there seems to be no immediate solution as the arrivals continue to swell day after day with more farmers across the country getting into chilli cultivation. The price drop has already resulted in the Centre announcing market intervention steps in Andhra Pradesh.

Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah has now written to Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivaraj Singh Chauhan for a similar step for chilli growers in Karnataka.

"I write to you with deep concern for the lakhs of red chilli farmers in Karnataka, particularly in the Kalyana Karnataka region, who are facing an unprecedented crisis due to the drastic fall in market prices," he said in his letter.

Chilli bags kept for auction at the Byadgi APMC yard. GIRISH PATTANASHETTI

He pointed out that the Government of India had approved the Price Deficiency Payment scheme under the Market Intervention Scheme for Red Chillies (Guntur Variety) in Andhra Pradesh, fixing the Minimum Intervention Price (MIP) at ₹11,781 per quintal with coverage for up to 25% of production. "While this is a welcome step, the distress faced by Karnataka's red chilli farmers remains unaddressed," he wrote.

The Chief Minister demanded an increase in MIP to ₹13,500 per quintal terming the current MIP of ₹ 11,781 per quintal as inadequate considering the rising input costs and the significantly higher cost of production in Karnataka. He also demanded expanding coverage to at least 75% of production.

Former Chief Minister Basavaraj Bommai also wrote a similar letter to Mr. Chauhan soon after.

Chamaras Malipatil, Honorary President of Karnataka Raita Sangha, demanded that the government fix MIP up to ₹15,000 and above per quintal to help farmers. "We will raise this issue during Chief Minister's future scheduled meeting," he said.

There are other initiatives in the offing too. "The State government earmarked ₹25 crore to establish a red chilli market in 10 areas of land in Raichur and tender was floated. The work is expected to be completed by the end of December 2025. Farmers can sell the product at the same price as in the Bydagi and Guntur markets. They can save transportation and vehicle halting charges and other labour expenditure," says Adappa, additional Director, APMC Raichur.

Long-term solution

But Morigeri believes that in the long run, only a reduction in arrivals and shifting to other crops, resulting in quality yield may see an increase rise in the prices in the coming years.

(With inputs from Ravikumar Naraboli in Yadgir)

Vehicles on fire after a mob, comprising mainly farmers, resorted to violence following the sudden fall in the prices of different varieties of chillies, at the APMC yard in Byadgi in March 2024. FILE PHOTO

ब्याडगी मिर्च: प्रमुख जानकारी

- **उत्पत्ति और खेती**

- मुख्य रूप से कर्नाटक के ब्याडगी और आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है।
- अच्छी जल निकासी वाली लाल और काली मिट्टी में गर्म जलवायु के तहत इसकी खेती होती है।

- **विशेषताएँ**
  - अपनी गहरी लाल रंगत और झुर्रीदार बनावट के लिए प्रसिद्ध।
  - हल्की तीखी लेकिन उच्च रंजकता (कैप्सैंथिन) के कारण गहरा लाल रंग प्रदान करती है।
- **कृषि पद्धतियाँ**
  - मध्यम सिंचाई और संतुलित कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
  - दिसंबर से मार्च के बीच इसकी कटाई की जाती है।
- **आर्थिक महत्व**
  - मसाला मिश्रण, ओलियोरेसिन निष्कर्षण और खाद्य रंग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
  - महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद, लेकिन हाल ही में कीमतों में उतार-चढ़ाव ने किसानों को प्रभावित किया है।
- **चुनौतियाँ**
  - निर्यात अस्वीकृति, विशेष रूप से कीटनाशक अवशेषों के कारण।
  - मूल्य अस्थिरता – अधिक उत्पादन और भंडारण की अधिकता के कारण कीमतों में गिरावट।

ब्याडगी मिर्च के किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार और कृषि विशेषज्ञों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

GEO IAS
It's about quality

In News : ASEAN

हाल ही में 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus) आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह (EWG on CT) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बैठक के प्रमुख बिंदु

- मलेशिया (2026) में टेबल-टॉप आतंकवाद विरोधी अभ्यास और भारत (2027) में फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास आयोजित किया जाएगा।
- भारत और मलेशिया ने 2024-2027 के लिए EWG on CT की सह-अध्यक्षता संभाली है।
- यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में हिंसक उग्रवाद को रोकने और मुकाबला करने पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें भारत-ईयू आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया गया।

आसियान (ASEAN) क्या है?

- आसियान (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **स्थापना:** 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड
- **स्थापना समझौता**: बैंकॉक घोषणा
- **मूल सदस्य देश:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड
- **बाद में जुड़े सदस्य:** ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस और म्यांमार (1997), कंबोडिया (1999)
- **मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया
- **आसियान का आदर्श वाक्य:** "One Vision, One Identity, One Community"
- **आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति (2022):**
  - **कुल जनसंख्या:** 662 मिलियन
  - **संयुक्त GDP:** $3.2 ट्रिलियन

आसियान की संस्थागत व्यवस्था

- **आसियान शिखर सम्मेलन:** क्षेत्रीय मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए वार्षिक बैठक।
- **आसियान समन्वय परिषद (ACC):** आसियान समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी।
- **आसियान सचिवालय:** संगठन की गतिविधियों और पहलों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
- **आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF):** राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर संवाद मंच।
- भारत 1996 में इसमें शामिल हुआ।
- **निर्णय-निर्माण प्रक्रिया:** परामर्श और आम सहमति पर आधारित।

भारत-आसियान संबंध

- **1992:** भारत आसियान का सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बना।

- **1996:** भारत आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) में शामिल हुआ और पूर्ण संवाद भागीदार बना।
- **2009:** भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) - वस्तुओं के लिए।
- **2012**: भारत और आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई।
- **2014**: सेवाओं और निवेश के लिए FTA समझौता।
- **भारत ADMM-Plus (**आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

आसियान फ्यूचर फोरम

- वियतनाम द्वारा 2023 (43वें आसियान शिखर सम्मेलन) में प्रस्तावित।
- आसियान सदस्य देशों और भागीदारों के लिए एक साझा मंच, जहां नीति सिफारिशें और विचार साझा किए जाते हैं।
- भारत इस मंच का संस्थापक सदस्य है।

भारत-आसियान सहयोग, विशेष रूप से रक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 08 Editorial Analysis

India's marginalised Parliament in budgetary affairs

The Budget is more than just a financial statement, as it reflects a nation's priorities, economic vision and governance philosophy. Across democracies, parliaments exercise the power of the purse, which is critical in shaping national budgets, ensuring fiscal discipline, and promoting transparency. However, in India, parliamentary influence over the Budget remains minimal. The executive-driven process side lines legislators, leaving them with little opportunity to effectively shape or scrutinise financial policies. Parliament must evolve from being a mere approver of the government's financial proposals to actively shaping economic policy. This requires critical institutional reforms, including pre-Budget discussions and establishing a Parliamentary Budget Office (PBO).

The Budget, a pillar of democracy

Budgeting is a fundamental democratic exercise that allocates public resources and defines the government's social and economic priorities. Historically, the power of the purse has been hard-won, with legislatures across the world asserting their right to oversee public finance. From the British Parliament's financial control in the 19th century to the fiscal policies of modern democracies, legislative scrutiny has been essential in preventing executive overreach.

Globally, the degree of legislative influence over budgets varies. Some parliaments actively draft and modify budget proposals, while others act as rubber stamps. Certain legislatures hold in-depth committee discussions on budgetary allocations, whereas others rely on centralised finance committees. However, one common thread remains – Budget transparency and parliamentary engagement correlate with better social outcomes and economic stability.

Parliament's role in Budget formulation and scrutiny in India is mainly ceremonial. The Finance Ministry single-handedly crafts the Budget, keeping even Cabinet Ministers uninformed until its presentation in the Lok Sabha. Unlike other legislative Bills, the Budget proposal is not subjected to thorough cabinet discussions before being introduced in Parliament. The executive monopoly over financial planning results in fragmented debates and limited oversight, weakening the core tenets of representative democracy.

Vinod Bhanu

is the Executive Director of the Centre for Legislative Research and Advocacy (CLRA), New Delhi

The existing budgetary process diminishes the role of elected representatives, undermining democratic accountability

Moreover, the Rajya Sabha, despite its democratic credentials, has no substantive role in Budget discussions. Ironically, while India permits a Finance Minister to be a Rajya Sabha member, they lack the ability to vote on their (own) Budget proposals in the Lok Sabha. This absence of budgetary bicameralism contrasts sharply with the British House of Lords, which wields some influence over financial legislation despite being an unelected body.

The decline of parliamentary authority over budgetary matters is evident in the poor quality and brevity of debates and the ineffective scrutiny by subject committees. Parliamentarians lack the power to amend or significantly influence budget proposals, effectively reducing their role to passive approval. This status quo is neither democratic nor conducive to accountability.

Pre-Budget discussions

Two key reforms must be implemented for Parliament to reclaim its rightful role in Budget-making: introducing pre-budget discussions and creating a Parliamentary Budget Office.

Parliament should institutionalise pre-Budget discussions during the monsoon session to ensure meaningful engagement in the Budget process. A dedicated five to seven-day discussion period would allow legislators to assess the nation's fiscal health, outline Budget priorities, and present a broad economic framework for the government's consideration. Such discussions would also encourage better coordination among subject committees, enhancing their ability to provide informed input.

Pre-Budget debates would democratise the Budget-making process, allowing elected representatives to voice public concerns, suggest equitable resource allocation, and engage in policy deliberations. More importantly, they would facilitate greater public involvement, fostering transparency and trust in financial governance.

Scepticism about active legislative involvement in budgeting often stems from concerns over fiscal discipline. Some economists argue that empowering legislatures may lead to populist spending and weakened financial prudence. However, placing unchecked faith in the executive to act in the public interest is naive. Regardless of ideology, no government has ever voluntarily ensured economic justice without oversight. A balanced approach, where the executive retains financial discretion but remains answerable to Parliament, is the hallmark of a healthy democracy.

A crucial aspect of Budget reform is in strengthening Parliament's analytical and research capabilities. India lacks an institutional mechanism that provides legislators with independent and non-partisan Budget analysis. Establishing a Parliamentary Budget Office (PBO) would bridge this gap as there would be data-driven insights and expert economic forecasts. Modelled on institutions such as the U.S. Congressional Budget Office and similar bodies in Australia, Canada and the United Kingdom, a well-structured PBO in India would play a vital role in analysing government spending, revenue projections, and fiscal policies. It would conduct independent economic forecasts, assess the fiscal impact of proposed policies, and evaluate medium-term and long-term budgetary trends.

Additionally, the PBO would offer policy briefs to parliamentarians, enhancing informed decision-making. Rather than encroaching upon the executive's role, it would complement it by ensuring legislative scrutiny is backed by objective research. Such an institution would significantly enhance Parliament's capacity to hold the government accountable and foster evidence-based policy discussions.

Reclaiming parliamentary authority

The current budgetary process diminishes the role of elected representatives, undermining democratic accountability. By integrating pre-Budget discussions and establishing a PBO, Parliament can transition from being a passive recipient of financial proposals to an active budget-influencing institution.

These reforms are procedural adjustments and fundamental steps towards strengthening representative democracy. They would ensure public finance decisions reflect collective deliberation rather than executive fiat. A robust parliamentary engagement in budgeting would ultimately lead to more equitable economic policies, greater transparency, and a financial governance framework that genuinely serves the people's interests.

Paper 02:Indian Polity

UPSC Mains Practice Question: भारत की बजटीय प्रक्रिया में संसद की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। बजट बनाने की कार्यपालिका द्वारा संचालित प्रकृति राजकोषीय पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कैसे प्रभावित करती है?

Context :

- राष्ट्रीय बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि यह किसी देश की आर्थिक दृष्टि, शासन दर्शन और नीतिगत प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है।
- लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की अवधारणा मौलिक होती है, जो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- हालांकि, भारत में बजट प्रक्रिया मुख्य रूप से कार्यपालिका-प्रधान है, जिसमें संसद की भूमिका अत्यंत सीमित है।
- इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि पूर्व-बजट चर्चाएं (Pre-Budget Discussions) और संसदीय बजट कार्यालय (Parliamentary Budget Office - PBO) की स्थापना, जिससे विधायी निगरानी को मजबूत किया जा सके और वित्तीय प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके।

बजट: लोकतंत्र का एक स्तंभ

- बजट एक वित्तीय खाका होता है, जो संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करता है और सरकार की आर्थिक व सामाजिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- ऐतिहासिक रूप से, सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण लोकतांत्रिक शासन का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है, जिससे कार्यपालिका की मनमानी रोकी जा सकती है।
- विश्वभर में अलग-अलग लोकतंत्रों में बजट निर्माण में विधायिका की भूमिका भिन्न-भिन्न होती है:
- कुछ देशों में संसद बजट प्रस्तावों को सक्रिय रूप से संशोधित और तैयार करती है।
- वहीं कुछ देशों में संसद केवल सरकारी प्रस्तावों को सीमित समीक्षा के बाद मंजूरी देती है।
- एक सामान्य प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि बजट प्रक्रिया में विधायिका की अधिक भागीदारी से आर्थिक स्थिरता और सामाजिक लाभ बेहतर होते हैं।

भारत की बजट प्रक्रिया की संरचनात्मक कमजोरियां

- **बजट निर्माण पर कार्यपालिका का एकाधिकार**
  - अन्य विधायी प्रस्तावों के विपरीत, बजट पूरी तरह से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें संसद की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती।
  - वित्त मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह बजट की योजना बनाते हैं, जबकि अधिकांश कैबिनेट मंत्री भी अंतिम प्रस्तुति से पहले अनजान रहते हैं।
  - यह गोपनीयता उन लोकतांत्रिक देशों से विपरीत है, जहां विधायिका को प्रारंभिक बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

अन्य देशों की तुलना

- **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)**
  - कांग्रेस समितियां पूर्व-बजट चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

    - राष्ट्रपति का बजट प्रस्ताव अनुमोदन से पहले गहन समीक्षा और बहस से गुजरता है।
- **जर्मनी और स्वीडन**
    - संसदीय समितियां बजट प्रस्तावों का आकलन पहले ही कर लेती हैं, जिससे सांसद वित्तीय नीतियों को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं।
- **भारत में स्थिति**
    - बजट के प्रस्तुत होने तक इसकी मुख्य रूपरेखा तैयार हो चुकी होती है।
    - इसका परिणाम यह होता है कि संशोधन और गहन चर्चा की कोई वास्तविक गुंजाइश नहीं बचती।

बजट पर बहस और समीक्षा के लिए सीमित समय

- बजट पेश किए जाने के बाद इसे संसद में बहस, समीक्षा और अनुमोदन के लिए बहुत कम समय दिया जाता है।
- संसद में बजटीय आवंटनों पर चर्चा अक्सर संक्षिप्त और सतही होती है।
- बजट फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है, और इसे मार्च के अंत तक पारित करना आवश्यक होता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय आवंटनों का गहन विश्लेषण करने के लिए यह समय-सीमा अपर्याप्त होती है।

संसदीय समितियों की सीमित भूमिका

- यद्यपि संसदीय स्थायी समितियों (Standing Committees) को बजट की समीक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इनका प्रभाव सीमित है।
- विभाग-संबंधी स्थायी समितियां (DRSCs) विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की समीक्षा करती हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।
- सरकार स्वतंत्र रूप से उनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर सकती है, जिससे संसदीय समिति की समीक्षा प्रभावहीन हो जाती है।
- अन्य देशों की तुलना
- कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में संसदीय समितियां बजट विश्लेषण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती हैं।
- इन देशों में स्वतंत्र बजट कार्यालय होते हैं, जो विधायकों को स्वतंत्र आर्थिक शोध और विश्लेषण प्रदान करते हैं।

राज्यसभा की सीमित भूमिका

- भारत में बजट प्रक्रिया की एक बड़ी संरचनात्मक कमजोरी राज्यसभा (ऊपरी सदन) की सीमित भूमिका है।
- संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, बजट एक मनी बिल (Money Bill) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्य रूप से लोकसभा (निचले सदन) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- एक बार जब लोकसभा बजट पारित कर देती है, तो राज्यसभा केवल उस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती।

बजट में संशोधन का कोई अधिकार नहीं

- भारतीय संसद के पास बजट में संशोधन या बदलाव करने की कोई वास्तविक शक्ति नहीं है।
- सांसद आपत्तियां उठा सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से खर्च या कर-नीतियों में बदलाव नहीं कर सकते।
- फ्रांस और स्वीडन जैसे देशों में, सांसदों को वैकल्पिक व्यय आवंटन प्रस्तावित करने का अधिकार होता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

संभावित सुधार: संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करने के उपाय

- **पूर्व-बजट चर्चाओं की आवश्यकता**
    - संसद में पूर्व-बजट चर्चाओं को संस्थागत रूप देना आवश्यक है।

  - मॉनसून सत्र के दौरान आयोजित की जाने वाली इन चर्चाओं से सांसद देश की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकेंगे और बजटीय प्राथमिकताओं पर चर्चा कर सकेंगे।
  - एक समर्पित 5 से 7 दिन की बहस संसद में वित्तीय आवंटन को अधिक पारदर्शी और समावेशी बना सकती है।
- **संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना**
  - वर्तमान में, भारत में कोई स्वतंत्र संस्थागत तंत्र नहीं है जो सांसदों को बजट विश्लेषण की निष्पक्ष और विस्तृत जानकारी प्रदान कर सके।
  - PBO, अमेरिका के Congressional Budget Office (CBO) और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद इसी तरह की संस्थाओं की तर्ज पर स्थापित किया जाना चाहिए।
  - यह कार्यालय बजटीय व्यय, राजस्व अनुमानों और वित्तीय नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन करेगा और सांसदों को शोध-आधारित नीति सुझाव प्रदान करेगा।

निष्कर्ष: संसद की भूमिका को पुनः स्थापित करना

- वर्तमान बजट प्रक्रिया में संसद की सीमित भूमिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है।
- पूर्व-बजट चर्चाओं को लागू करके और PBO की स्थापना करके, संसद को बजट प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा सकता है।
- ये सुधार केवल प्रक्रियात्मक परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक वित्तीय प्रशासन को मजबूत करने के महत्वपूर्ण कदम हैं।
- इन सुधारों से बजटीय निर्णयों में सामूहिक विचार-विमर्श को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिक न्यायसंगत आर्थिक नीतियां तैयार की जा सकेंगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा।

यदि संसद सार्वजनिक वित्त पर अपनी वास्तविक शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती है, तो यह भारत की आर्थिक और लोकतांत्रिक अखंडता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

GEO IAS
It's about quality